परमेंदर कुमार और अन्य

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य।

(सिविल अपील संख्या 9717/2011)

14 नवंबर 2011

[अल्तमस कबीर, साइरियक जोसेफ और सुरिंदर सिंह निज्जर, जे.जे.]

शिक्षा/शैक्षिक संस्थान- चिकित्सा में स्नातकोत्तर या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश- प्रवेश से संबंधित शर्तें जैसा कि प्रॉस्पेक्टस में दर्शाया गया है - परिणाम की घोषणा और चयन सूची तैयार होने के बाद राज्य सरकार द्वारा शर्तों में संशोधन - अभिधारण करने की शक्ति प्रॉस्पेक्टस प्रकाशित होने पर ऐसे सरकारी आदेश पहले से ही लागू थे, उनका निश्चित रूप से प्रवेश प्रक्रिया पर असर पड़ेगा - हालाँकि, एक बार परिणाम घोषित हो जाने और एक चयन सूची तैयार हो जाने के बाद, राज्य सरकार के लिए इसमें बदलाव करना संभव नहीं था। काउंसलिंग शुरू होने से ठीक एक दिन पहले नियम और शर्तें, ताकि पहले से चयनित उम्मीदवारों को उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के अवसर से वंचित किया जा सके - आरक्षित श्रेणी में प्रवेश का लाभ द्वारा अपनाई गई नीति का परिणाम है राज्य सरकार ने लिखित परीक्षा के परिणामों को ध्यान में रखते हुए योग्यता के आधार पर

आरक्षित श्रेणी के अपीलकर्ताओं के उम्मीदवारों के लिए प्रावधान किया है, यह प्रस्तुत करते हुए कि आरक्षित श्रेणी में ऐसे प्रवेश आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किए जाने होंगे। संस्थान में शिक्षा के स्तर को बनाए रखने को स्वीकार नहीं किया जा सकता

अपीलकर्ता-राज्य सिविल चिकित्सा सेवाओं के सदस्य, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार हैं

हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज (एचसीएमएस) आरक्षित कोटा के तहत एक विश्वविद्यालय, प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, एचसीएमएस कोटा के लिए आरक्षित सीटों के साथ-साथ ओपन मेरिट श्रेणी के तहत सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी, बी परिणाम घोषित किए गए थे। और काउंसलिंग आयोजित की गई. प्रॉस्पेक्टस के खंड 5 और 6 में प्रावधान है कि एचसीएमएस डॉक्टर जो एचसीएमएस आरक्षित कोटा के तहत पीजी-पाठ्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें 5 दिसंबर, 2008 के हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार एनओसी की आवश्यकता है; और सी परिवीक्षा अवधि के सफल समापन के साथ तीन साल की नियमित सेवा। इसके आधार पर, अपीलकर्ताओं को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई, उनके नाम 3 मार्च, 2011 की मेरिट सूची में प्रकाशित किए गए

और उन्हें प्रवेश दिया गया। हालाँकि, 31 मार्च, 2011 को, हरियाणा सरकार ने एक निर्देश जारी किया जिसने पात्रता शर्तों को बदल दिया, जिसके तहत तीन साल की नियमित सेवा को पांच साल में बदल दिया गया और इसे प्रवेश की प्रक्रिया में लागू किया गया जो पहले से ही आधार पर निर्धारित की गई थी। पिछली सरकार के निर्देश, और वह भी काउंसलिंग की तारीख से ठीक एक दिन पहले। व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस आशय का एक अंतरिम आदेश पारित किया कि इस बीच अपीलकर्ताओं को अपने जोखिम और जिम्मेदारी के अधीन, एचसीएमएस कोटा उम्मीदवारों के खिलाफ काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी; और यह कि उक्त आदेश अपीलकर्ताओं के पक्ष में कोई न्यायसंगत अधिकार प्रदान नहीं करेगा। खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा।

इन अपीलों में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह है कि क्या राज्य सरकार के पास चिकित्सा के विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित शर्तों को बदलने का कोई अधिकार क्षेत्र और/या अधिकार है, जो पहले प्रॉस्पेक्टस में दर्शाया गया था। , एक बार

ऐसे प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी और परिणाम घोषित किए गए थे और उसके आधार पर एक चयन सूची भी तैयार की गई थी।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए अभिनिर्धारित:

1.1. अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि एक बार प्रॉस्पेक्टस के आधार पर स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई, उसके बाद, प्रॉस्पेक्टस में निहित प्रावधानों को बदलने के लिए सरकारी आदेशों द्वारा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। . यदि प्रॉस्पेक्टस प्रकाशित होने के समय ऐसे सरकारी आदेश पहले से ही लागू थे, तो निश्चित रूप से प्रवेश प्रक्रिया पर उनका असर होगा, लेकिन एक बार परिणाम घोषित हो जाने और चयन सूची तैयार हो जाने के बाद, राज्य सरकार के लिए इसमें बदलाव करना संभव नहीं था। काउंसलिंग शुरू होने से ठीक एक दिन पहले नियम और शर्तें, ताकि पहले से ही चयनित उम्मीदवारों को उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के अवसर से वंचित किया जा सके। आरक्षित वर्ग में प्रवेश के कई लाभ हैं, लेकिन यह राज्य सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को प्रदान करने के लिए अपनाई गई नीति का परिणाम है और चूंकि अपीलकर्ताओं का चयन योग्यता के आधार पर किया गया था, जिसे ध्यान में रखते हुए लिखित

परीक्षा के परिणाम के आधार पर यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती कि आरक्षित वर्ग में ऐसे प्रवेश संस्थान में शिक्षा के मानक को बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। अपीलकर्ताओं ने लिखित परीक्षा में अपने परिणामों के आधार पर चयनित होकर अपनी योग्यता दिखाई है। यह दलील कि अपीलकर्ताओं को खुली श्रेणी से एनओसी दी गई थी, इस अदालत में अपील नहीं करती है, क्योंकि अपीलकर्ता एचसीएमएस की आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार थे। [पैरा 23] [1079-ई-एच: 1080-ए-डी]

उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम ममता मोहंती **(2011) 3 एससीसी 436 2011 (2) एससीआर 704- प्रतिष्ठित।**

1.2 उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले और आदेश को रद्द किया जाता है। हालाँकि, इन अपीलों में काउंसलिंग प्रक्रिया 6 अप्रैल, 2011 को आयोजित की जानी थी और शैक्षणिक सत्र 10 मई, 2011 को शुरू होना था। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता पहले ही विचाराधीन पाठ्यक्रमों के लगभग छह महीने खो चुके हैं। जैसा कि डॉ. विनय रामपाल के मामले में देखा गया, समय की रेत ख़त्म हो चुकी थी जो न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य है। उसी तर्क का पालन करते हुए, जैसा कि डॉ. विनय रामपाल के मामले में अपनाया गया था, यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ताओं को नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातकोत्तर या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश

दिया जाएगा, जिसके लिए उनका चयन किया गया है। बिना किसी अतिरिक्त परीक्षण या चयन के वर्ष। [पैरा 24] [1080-डी-जी]

विनय रामपाल (डॉ) बनाम। जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य। **(1984) 1 एससीसी 160-पर निर्भर।**

पंजाब राज्य और अन्य। बनाम डॉ. विनय कुमार खुल्लर एवं अन्य। **(2010) 13 एससीसी 481: 2010 (13) एससीआर 733;** राजीव कपूर और अन्य। बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य। **(2000) 9 एससीसी 115: 2000 (2) एससीआर 629;** लोक सेवा आयोग संघ बनाम गौरव द्विवेदी एवं अन्य। **(1999) 5 एससीसी 180: 1999 (3) एससीआर 649;** अमरदीप सिंह सहोता बनाम. पंजाब राज्य **(1993) 4 एसएलआर 673 (एफबी)**

केस कानून संदर्भ:

2010 (13) एससीआर 733 करने के लिए भेजा.. पैरा 11, 13

(1984) 1 एससीसी 160 करने के लिए भेजा पैरा 13

2000 (2) एससीआर 629 करने के लिए भेजा पैरा 14

1999 (3) एससीआर 649 **करने के लिए भेजा**

पैरा 16

2011 (2) एससीआर 704 **प्रतिष्ठित**

पैरा 23

(1993) 4 एसएलआर 673 (एफबी) संदर्भित पैरा 21

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 9717/2011।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में 2011 के एलपीए नंबर 983 के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 2.6.2011 से उत्पन्न।

साथ

सीए 2011 की संख्या 9718, 9719, 9720, 9721 और 9722

उपस्थित पक्षों के लिए अलताफ अहमद, पी.एस. पाटवालीया, विकास सिंह, के.के. त्यागी, इफ्तेकार अहमद, पी नरसिंमन, डाॅ. कैलाश चंद, जगजीत सिंह, छाबरा, आर.के.गुप्ता, एस.के.गुप्ता, मुकेश सिंह, शेखर कुमार, डाॅ. मोनिका गुसैन, धर्मराज ओहलन, अतिशी दीपांकर

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

अल्तमस कबीर, जे. 1. छह विशेष अनुमति याचिकाएँ, एसएलपी (सी) संख्या 15974/2011, एसएलपी (सी) संख्या 16075/2011, एसएलपी (सी) संख्या। 16346/2011, एसएलपी (सी) संख्या 16228-30/2011 को

सुनवाई के लिए एक साथ लिया गया है, क्योंकि उनमें विशेष अनुमति याचिकाकर्ताओं की पात्रता से संबंधित तथ्य और कानून के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, जो हरियाणा सिविल मेडिकल के सदस्य हैं। सेवाएँ, पं. द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। पंडित बी डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक, प्रतिवादी संख्या 2, ऐसे उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटा के विरुद्ध।

2 अनुमति दी गई.

3. आगे बढ़ने से पहले, प्रतिवादी के रूप में इन कार्यवाहियों में शामिल होने के लिए डॉ. राजीव कुमार और 10 अन्य द्वारा एसएलपी (सी) संख्या 15974 में दायर 2011 के I.A.Nos.4 और 5 को अनुमति दी जाती है।

4. सुविधा के लिए हम डॉ. परमेंदर कुमार और अन्य द्वारा एसएलपी (सी) संख्या 15974/2011 से तथ्यों का हवाला देंगे जैसा कि ऊपर बताया गया है, सभी अपीलकर्ता ये अपीलें पद पर प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की हैं- प्रतिवादी संख्या 2 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक पाठ्यक्रम हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज (एचसीएमएस) बी आरक्षित कोटा के तहत । जैसा कि 6 जनवरी, 2011 के प्रॉस्पेक्टस द्वारा प्रदान किया गया था, उन उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी, जिन्होंने एचसीएमएस कोटा के लिए आरक्षित सीटों के साथ-साथ खुली

सीटों के लिए प्रवेश के लिए आवेदन किया था। योग्यता श्रेणी प्रॉस्पेक्टस प्रत्येक कोर्स में सीटों की कुल संख्या और एचसीएमएस आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सीटों और ओपन मेरिट के संबंध में भी निर्धारित करता है। प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, विभिन्न विषयों में पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स के लिए उपलब्ध सीटें कुल 145 सीटें उपलब्ध दर्शाती हैं, जिनमें से 73 सीटें अखिल भारतीय डी कोटा के लिए आरक्षित थीं, 29 सीटें एचसीएमएस आरक्षित कोटा के लिए आरक्षित थीं और 43 सीटें ओपन मेरिट श्रेणी के लिए सीटें आरक्षित थीं। प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 24 जनवरी, 2011 शाम 5 बजे तक थी। सामान्य प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 मार्च, 2011 को आयोजित की गई और परिणाम 3 मार्च, 2011 को घोषित किए गए। काउंसलिंग 6 अप्रैल, 2011 को निर्धारित की गई थी और शैक्षणिक सत्र 10 मई, 2011 को शुरू होने वाला था।

5. एचसीएमएस आरक्षित कोटा के के संबंध में प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रॉस्पेक्टस में निर्धारित पात्रता मानदंड को प्रॉस्पेक्टस के खंड 5 में शामिल किया गया था, जो इस प्रकार है:

> "5. राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित एचसीएमएस डॉक्टर। इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि वे अपने

नियोक्ता के माध्यम से आवेदन जमा करें या एनओसी प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन विभाग/राज्य सरकार को समय पर जमा करें और विभाग/राज्य सरकार। यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां भी पात्र हों, एनओसीएस पहली काउंसलिंग की तारीख यानी 06.04.2011 से पहले जारी किए जाएं।"

6. जो महत्वपूर्ण है वह चयन और प्रवेश की विधि है जिसे प्रॉस्पेक्टस का हिस्सा बनाया गया था, जिसमें योग्यता के निर्धारण से संबंधित खंड 6 में, उप-खंड (iii) में, इसे निम्नानुसार दर्शाया गया था:

"6.(iii) पीजी पाठ्यक्रमों में शामिल होने के इच्छुक एचसीएमएस डॉक्टरों के लिए हरियाणा सरकार के पत्र संख्या 2/123/05/1-एचबी-I दिनांक 5.12.2008 के तहत एनओसीएस के लिए तय की गई शर्तें अनुबंध में दी गई हैं। -डी. (हालांकि, समय-समय पर जारी नवीनतम सरकारी निर्देशों का पालन किया जाएगा)।"

7. उपरोक्त उप-खंड के अनुसार, एचसीएमएस डॉक्टर जो एचसीएमएस आरक्षित कोटा के तहत पीजी-पाठ्यक्रमों में शामिल होना चाहते थे, उन्हें हरियाणा सरकार के 5 दिसंबर, 2008 के निर्देशों के

अनुसार एनओसी की आवश्यकता थी। उक्त निर्देशों के अनुसार, एक पात्रता की शर्तें खंड 3 में निहित थीं, जिन्हें यहां नीचे दिया गया है:

> "3. पात्रता के लिए मूल शर्त परिवीक्षा अवधि के सफल समापन के साथ तीन साल की नियमित सेवा है, जिसमें से एचसीएमएस डॉक्टरों के मामले में आरक्षित और खुली दोनों सीटों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में दो साल की सेवा आवश्यक है। हालाँकि, ग्रामीण सेवा की शर्त एचएमईएस के सदस्य के मामले में लागू नहीं होगी।"

8. अपीलकर्ताओं को उपरोक्त मानदंड के आधार पर चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी और कई अपीलों में किए गए मामलों के अनुसार, उनके नाम 3 मार्च, 2011 की मेरिट सूची में प्रकाशित किए गए थे। उक्त सूची से यह दिखाई देगा कि M.D./M.S./P.G में HCMS कोटा में कुल 38 उम्मीदवारों में से। डिप्लोमा पाठ्यक्रम और एमडीएस पाठ्यक्रम में 3 उम्मीदवारों को, विभिन्न अपीलों में सभी अपीलकर्ताओं को समान उम्मीदवारों के साथ प्रवेश दिया गया।

9. हालाँकि, 31 मार्च, 2011 को, हरियाणा सरकार ने एक निर्देश जारी किया, जिसे 5 अप्रैल, 2011 को अपनी वेबसाइट पर प्रसारित किया गया, जिससे पात्रता बदल गई

एक शर्त और इसे प्रवेश की प्रक्रिया पर लागू किया गया जो पहले से ही 5 दिसंबर, 2008 के सरकारी निर्देशों के आधार पर शुरू की गई थी, और वह भी काउंसलिंग की तारीख से सिर्फ एक दिन पहले, यानी 6 अप्रैल, 2011 को। संशोधित प्रावधान यहां नीचे दिया गया है:

> "एमबीबीएस डॉक्टर 2 साल की परिवीक्षा सहित 5 साल की नियमित संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स, डिग्री और डिप्लोमा दोनों करने के लिए पात्र होंगे, जिसमें से 3 साल की सेवा जिला अस्पताल या किसी एक में होनी चाहिए। उप-विभागीय अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्र के संस्थानों में 2 वर्ष। केवल इस शर्त को पूरा करने वाले व्यक्ति ही पीजीआईएमएस रोहतक या अन्य सरकारी संस्थान में आरक्षित सीट के लिए और हरियाणा के सरकारी कॉलेजों या कहीं और इसी तरह के सरकारी संस्थानों में खुली सीटों के लिए प्रायोजन के लिए पात्र होंगे। देश में।"

10. यह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित बदली हुई शर्तें हैं, जिसके परिणामस्वरूप डॉ. परमेंद्र कुमार और अन्य द्वारा 2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 6168 दाखिल की गई और पंजाब में अन्य अपीलकर्ताओं द्वारा अन्य रिट याचिकाएं दायर की गईं। और हरियाणा उच्च न्यायालय। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता से संबंधित मूल शर्तों और

31 मार्च, 2011 के सरकारी निर्देश द्वारा किए गए परिवर्तनों पर विचार करने पर, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 6 अप्रैल, 2011 के आदेश द्वारा सूचीबद्ध करते हुए, मामले ने 13 मई, 2011 को इस आशय का एक अंतरिम आदेश पारित किया कि इस बीच अपीलकर्ताओं को अपने जोखिम और जिम्मेदारी के अधीन, एचसीएमएस कोटा उम्मीदवारों के खिलाफ काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। यह स्पष्ट कर दिया गया कि उक्त आदेश अपीलकर्ताओं के पक्ष में कोई न्यायसंगत अधिकार प्रदान नहीं करेगा। आगे यह निर्देश दिया गया कि अपीलकर्ताओं की काउंसलिंग का परिणाम एक सीलबंद कवर में रखा जाना चाहिए और यह रिट याचिका के नतीजे के अधीन होगा।

11. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश से व्यथित, डॉ. परमेंदर कुमार और अन्य ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष लेटर ए पेटेंट अपील संख्या 983 और 995/2011 दायर की। अपीलों का निपटारा डिवीजन बेंच ने अपने आदेश दिनांक 2 जून, 2011 द्वारा किया, जिसमें एनओसी देने से संबंधित नई नीति को चुनौती को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा गया, इस आधार पर कि यह स्पष्ट था कि राज्य ने एनओसी देने के लिए नीति निर्धारित करने का हर अधिकार, खासकर जब यह उच्च अध्ययन के लिए सेवाकालीन उम्मीदवारों के प्रायोजन के मामलों से निपट

रहा हो। इसके पीछे तर्क यह है कि राज्य चयनित एचसीएमएस उम्मीदवारों के लिए खर्च वहन करने के लिए प्रतिबद्ध था, क्योंकि ऐसे पदधारी पूर्ण वेतन के हकदार थे और इन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने में उनके द्वारा बिताई गई अवधि को ड्यूटी पर बिताई गई अवधि के रूप में माना जाएगा। डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि प्रॉस्पेक्टस को सही मानने में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि राज्य भाई-भतीजावाद में शामिल नहीं है, न ही दुर्भावना का कोई आरोप लगाया गया है, न ही वे दिखाई भी देते हैं। डिवीजन बेंच ने पाया कि अपीलकर्ताओं को विचार के क्षेत्र से बाहर नहीं किया गया था, लेकिन उन्हें एचसीएमएस श्रेणी में विचार करने से इनकार कर दिया गया था। डिवीजन बेंच ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि प्रॉस्पेक्टस में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि राज्य द्वारा समय-समय पर लागू नीति के अनुसार एनओसी जारी की जानी थी और इसके परिणामस्वरूप भले ही अपीलकर्ताओं ने प्रवेश के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की हो। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए, उन्हें हरियाणा राज्य से एनओसी प्राप्त करने या स्नातकोत्तर अध्ययन की अवधि के दौरान पूर्ण वेतन प्राप्त करने का कोई निहित अधिकार नहीं मिलता है। डिवीजन बेंच ने पंजाब राज्य और अन्य में इस न्यायालय के फैसले को अलग कर दिया। बनाम डॉ. विनय कुमार खुल्लर एवं अन्य। [(2010) 13 एससीसी 481], यह देखते हुए कि नीति संशोधित होने से पहले ही अनंतिम एनओसी जारी की जा

चुकी थी, जो वर्तमान मामले में इसकी प्रयोज्यता में निर्णय की विशिष्ट विशेषता थी।

12. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अल्ताफ अहमद और श्री के.के. त्यागी विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर भी सवाल उठाया उच्च न्यायालय की खंडपीठ के रूप में, इस आधार पर कि एक बार प्रॉस्पेक्टस में एक मानदंड निर्धारित कर दिया गया था, संबंधित उत्तरदाताओं के पास उक्त प्रॉस्पेक्टस के तहत प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसे बदलने का कोई अधिकार नहीं था और एक चयनित सूची अभ्यर्थियों को बी भी प्रकाशित किया गया था। अनुशासन का पालन करने के लिए काउंसलिंग से एक दिन पहले ऐसी शर्तों को बदलना, चयनित उम्मीदवारों के लिए पूर्वाग्रह था, क्योंकि उनका चयन असंशोधित प्रॉस्पेक्टस के आधार पर किया गया था। श्री अहमद ने प्रस्तुत किया कि कोई संभवतः प्रवेश के लिए मानदंड में सी परिवर्तन को स्वीकार कर सकता था, यदि यह प्रॉस्पेक्टस पर कार्रवाई करने से पहले किया गया होता, लेकिन एक बार प्रॉस्पेक्टस पर कार्रवाई हो जाने के बाद, स्नातकोत्तर में प्रवेश की पूरी प्रक्रिया या डिप्लोमा पाठ्यक्रम उक्त प्रॉस्पेक्टस द्वारा शासित होंगे और उसके बाद प्रॉस्पेक्टस की शर्तों में कोई भी बदलाव और/या बदलाव उन उम्मीदवारों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जिनका पहले ही चयन हो चुका है।

13. इस संबंध में, डॉ. विनय कुमार खुल्लर के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया था, जिसमें, चयन के लिए नियमों और ई शर्तों में बदलाव करते हुए लगभग एक समान मामले से निपटते समय, इस न्यायालय ने माना था कि इसके अलावा पहले के परिपत्रों के अनुसार, संशोधन परिपत्र का उल्लेख प्रॉस्पेक्टस में किया जाना चाहिए था। यह पाया गया कि सरकार को यह कहने से कोई नहीं रोक सका कि एनओसी 13 मई, 1996 के परिपत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन होनी चाहिए, जैसा कि 30 जुलाई, 2007 के परिपत्र द्वारा संशोधित किया गया था, जो 2007 के प्रवेश के बाद जारी किया गया था और मांगा गया था . 2008 के प्रवेश के संबंध में पहली बार लागू किया जाएगा। नतीजतन, 2008 के प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को 30 जुलाई, 2007 के संशोधन जी परिपत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, जब तक कि प्रॉस्पेक्टस में इसका उल्लेख नहीं किया गया हो। इस न्यायालय ने आगे कहा कि उम्मीदवारों को 13 मई, 1996 के सरकारी परिपत्र के अनुसार एनओसी के लिए पात्रता के आधार पर आगे बढ़ना होगा। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने डॉ. विनय रामपाल के मामले में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया था। डॉ. विजय रामपाल बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य. [(1984) 1 एससीसी 160], जिसमें इस न्यायालय ने माना था कि चूंकि विज्ञापन में 23 मार्च 1979 के बाद के

सरकारी आदेश के बारे में कोई संदर्भ नहीं दिया गया था, इसलिए विज्ञापन में निर्धारित आवश्यकता ही आधार प्रदान करनी चाहिए थी उसमें याचिकाकर्ता के प्रवेश के लिए चयन और पात्रता के लिए।

14. श्री अल्ताफ अहमद ने बताया कि एक अन्य मामले में, अर्थात् राजीव कपूर और अन्य। बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य। [(2000) 9 एससीसी 115], इस न्यायालय ने देखा था कि मुकदमेबाजी के कारण जो गड़बड़ी हुई थी, वह विश्वविद्यालय द्वारा प्रॉस्पेक्टस के अयोग्य प्रारूपण और प्रकाशन और बाध्यकारी आदेशों को ठीक से नहीं करने के कारण अधिक प्रतीत होती थी। सरकार और समय-समय पर पारित किए गए बहुत से आदेशों को टुकड़ों में स्वतंत्र रूप से खड़े रहने की अनुमति दी जा रही है। वास्तव में, यह भी देखा गया कि सरकार भविष्य में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में, आवेदन आमंत्रित करने से पहले ही, पूरी योजना का एक सार-संग्रह और चयन के आधार पर अद्यतन संशोधन और प्रॉस्पेक्टस भी प्रकाशित करेगी। , हर साल चयन के मामले में भ्रम से बचने के लिए, विशेष रूप से उन्हें प्रॉस्पेक्टस के हिस्से के रूप में अपनाना।

15. श्री अहमद ने प्रस्तुत किया कि चूंकि विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मानदंड में बाद में बदलाव को चालू वर्ष में प्रवेश के लिए प्रॉस्पेक्टस में शामिल नहीं किया

गया था, इसलिए उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। और उस ओर से किए गए प्रस्तुतीकरण अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।

16. दूसरी ओर, अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 2 से 11 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.एस. पटवालिया ने प्रस्तुत किया कि नए सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से पहले उम्मीदवार द्वारा एनओसी प्राप्त करने का निर्देश देने का उद्देश्य यह था कि विकल्प था इससे पहले कि ऐसे उम्मीदवारों को उस अवधि के लिए पूरा वेतन मिल जाए, जिसके दौरान उन्हें स्नातकोत्तर की पढ़ाई करनी थी, बेहद सावधानी से किया जाना चाहिए और उन्हें पूरी अवधि के दौरान सेवा में भी माना जाएगा।

एक अवधि तक। श्री पटवालिया ने प्रस्तुत किया कि प्रॉस्पेक्टस में संशोधन से पहले, उसके खंड 3 में प्रावधान था कि पात्रता के लिए बुनियादी शर्तें परिवीक्षा अवधि के सफल समापन के साथ 3 साल की नियमित सेवा होगी, जिसमें से 2 साल की सेवा ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक थी। क्षेत्र. एक उम्मीदवार के मामले में एक अपवाद बनाया गया था जो एचसीएमएस का सदस्य था। उक्त मानदंड को 5 दिसंबर, 2008 के सरकारी निर्देश द्वारा बदल दिया गया था, जिसके तहत यह संकेत दिया गया था कि एमबीबीएस सदस्य स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने के लिए पात्र होंगे। 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के बाद,

जैसा कि पहले निर्धारित किया गया था, 2 वर्ष की परिवीक्षा सहित, जिसमें से 3 वर्ष की सेवा जिला अस्पताल या उप-विभागीय अस्पताल में से एक में और 2 वर्ष की सेवा करनी होगी। एक ग्रामीण क्षेत्र संस्था. श्री पटवालिया ने प्रस्तुत किया कि उक्त परिवर्तन प्रवेश के लिए पात्रता के मानदंड के संबंध में कोई बदलाव नहीं था, बल्कि यह सेवा की शर्तों में बदलाव था क्योंकि सरकार के पास हमेशा ऐसे बदलाव करने की शक्ति होती है। इस संबंध में, श्री पटवालिया द्वारा इस न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा किया गया है i) लोक सेवा आयोग संघ बनाम। गौरव द्विवेदी और अन्य [(1999) 5 एससीसी 180] और (ii) उड़ीसा राज्य और अन्य। बनाम ममता ई मोहंती [(2011) 3 एससीसी 436], जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि शिक्षकों द्वारा निर्धारित योग्यता रखने की आवश्यकता एक शैक्षणिक संस्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की उत्कृष्टता मुख्य रूप से सीधे उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। एफ स्टाफ को पढ़ाने का। इसलिए, जब तक शिक्षकों का अकादमिक रिकॉर्ड अच्छा न हो, शिक्षा के स्तर को न तो बनाए रखा जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है।

17. श्री पटवालिया ने राजीव कपूर के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की आरक्षित श्रेणी से प्रवेश पाने वाले सेवाकालीन उम्मीदवारों के अधिकार

का प्रश्न विचाराधीन था। यह माना गया कि एचसीएमएस उम्मीदवारों में से चयन में अपनाई जाने वाली विधि और प्रक्रिया के संबंध में, सरकारी आदेश उन जी के अलावा अन्य प्रक्रिया प्रदान करते हैं प्रॉस्पेक्टस में निहित प्रावधान काफी वैध थे, क्योंकि इसमें ऐसे आदेश जारी करने की शक्ति थी और प्रॉस्पेक्टस सरकारी आदेशों को छोड़कर मान्य नहीं हो सकता था। विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि दोनों को इस प्रकार समझा जाना चाहिए कि सेवारत उम्मीदवारों की परस्पर योग्यताओं का मूल्यांकन उनकी साख और सेवा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाए। यह स्पष्ट रूप से माना गया कि भले ही नवीनतम सरकारी आदेश परिणाम घोषित होने के बाद जारी किया गया हो। प्रवेश परीक्षा के लिए पूर्व आदेश का अनुपालन करना अभी भी आवश्यक होगा

18. श्री पटवालिया ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर, अपीलें खारिज किये जाने योग्य थीं।

19. हरियाणा राज्य की ओर से, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह ने बताया कि एनओसी, जो सरकार द्वारा 4 अप्रैल, 2011 को दी गई थी, आरक्षित एचसीएमएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 5 के लिए दी गई थी। साल, जबकि ओपन कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 साल के लिए एनओसी दी गई थी. जहां तक अपीलकर्ताओं का सवाल है, उन्हें आरक्षित श्रेणी के लिए नहीं बल्कि खुली श्रेणी के लिए एनओसी दी गई थी और इसलिए,

आरक्षित एचसीएमएस श्रेणी में प्रवेश के लिए विचार किए जाने का उनका दावा बिना किसी आधार के था और खारिज किया जा सकता था।

20. बताए गए तथ्यों से, इन अपीलों में निर्णय के लिए एकमात्र प्रश्न यह उभरता है कि क्या राज्य सरकार के पास विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित शर्तों को बदलने का कोई अधिकार क्षेत्र और/या अधिकार था। चिकित्सा जो पहले प्रॉस्पेक्टस में इंगित की गई थी, एक बार ऐसे प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी और परिणाम घोषित किए गए थे और उसके आधार पर एक चयन सूची भी तैयार की गई थी। दूसरे शब्दों में, जब एक बार प्रॉस्पेक्टस में शामिल नियमों और शर्तों के आधार पर चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो क्या प्रवेश के लिए पात्रता से संबंधित मानदंड में बदलाव करना राज्य सरकार की क्षमता में था, जबकि न केवल ऐसा करना था। प्रॉस्पेक्टस के संदर्भ में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन यह भी जब काउंसलिंग अगले ही दिन आयोजित की जानी थी, जिसके परिणामस्वरूप कई उम्मीदवारों को आरक्षित एचसीएमएस श्रेणी में पोस्ट-ग्रेजुएट या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलने से वंचित होना पड़ा।

21. हालाँकि, श्री पटवालिया ने राजीव कपूर के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले पर काफी भरोसा किया था, जिसमें, तथ्य लगभग इस मामले के तथ्यों के समान थे, दोनों के बीच एक विलक्षण अंतर है दो।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय ने राजीव कपूर के मामले (सुप्रा) में यह माना है कि उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं के दावे को कायम रखने में गंभीर त्रुटि की है कि विचाराधीन पाठ्यक्रम के लिए चयन और प्रवेश होना ही था। केवल विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस के अध्याय V में निहित शर्तों के अनुसार। आगे यह माना गया कि ऐसी त्रुटि यह मानकर की गई थी कि सरकार के पास प्रॉस्पेक्टस में शामिल मानदंडों के अलावा कोई भी मानदंड निर्धारित करने के लिए कोई निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं था और केवल लिखित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक ही उचित मूल्यांकन का गठन करते हैं। चयन और प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का योग्यता प्रदर्शन। इस न्यायालय ने यह भी देखा कि रिट याचिकाओं को अनुमति देने में उच्च न्यायालय ने अमरदीप सिंह सहोता बनाम में रिपोर्ट किए गए उसी उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के पहले के फैसले का पालन करने का इरादा किया था। अमरदीप सिंह सहोता पंजाब राज्य ((1993) 4 एसएलआर 673 (एफबी)], जो वास्तव में, विशेष रूप से आरक्षित श्रेणी के संबंध में, पेशेवर कॉलेजों में पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रवेश के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए सरकार एफ की योग्यता या अधिकार पर संदेह नहीं करता था। सीटों की संख्या। इस न्यायालय ने यह भी देखा कि अंततः पूर्ण पीठ ने उसके द्वारा तय किए गए मामले में निर्देश दिया था कि प्रवेश

के लिए चयन को पहले से लागू सरकारी आदेशों और प्रॉस्पेक्टस में निर्दिष्ट मानदंड जी के आलोक में अनदेखा किया जाना चाहिए। बाद के चरण में बदलाव की पेशकश करने वाली अधिसूचना।

22. यदि इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय पर भरोसा किया जाए, तो यह वास्तव में अपीलकर्ताओं के मामले का पक्ष लेता है, क्योंकि यह देखते हुए कि एच में पाठ्यक्रमों के लिए चयन या प्रवेश प्रश्न को विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस में निहित शर्तों के अनुसार ही प्रभावी करना होगा, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों को भी ध्यान में रखना होगा। हालाँकि, लिखित प्रवेश परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद जारी किए गए आदेशों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा एक अपवाद बनाया गया था। उस संदर्भ में, इसे इस प्रकार देखा गया:

> .....इस तथ्य पर ध्यान न देने में और भी त्रुटि प्रतीत होती है कि दिनांक 21-5-1997 के आदेश, जो लिखित प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद जारी किए गए थे, भले ही उन आदेशों पर विचार न किया गया हो दिनांक 20-3-1996 और 21-2-1997 पिछले वर्षों के आदेशों की निरंतरता में पारित हुए, इस क्षेत्र को जारी रखा गया, क्योंकि दिनांक 21-5-1997 के आदेश केवल उसी की निरंतरता में थे।"

23. जैसा कि यहां पहले भी बताया गया है, इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि पूर्ण पीठ, जिसके फैसले पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया था, ने अंततः निर्देश दिया कि प्रवेश के लिए चयन को निर्दिष्ट मानदंडों के आलोक में अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। सरकारी आदेश पहले से ही लागू हैं और प्रॉस्पेक्टस, "आपत्तिजनक अधिसूचना को नजरअंदाज करने के बाद बाद के चरण में बदलाव की शुरुआत की गई है।" वास्तव में, अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि एक बार प्रॉस्पेक्टस के आधार पर स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसके बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। प्रॉस्पेक्टस में निहित प्रावधानों को बदलने के लिए सरकारी आदेशों द्वारा। यदि प्रॉस्पेक्टस प्रकाशित होने के समय ऐसे सरकारी आदेश पहले से ही लागू थे, तो निश्चित रूप से प्रवेश प्रक्रिया पर उनका असर होगा, लेकिन एक बार परिणाम घोषित हो जाने और चयन सूची तैयार हो जाने के बाद, राज्य सरकार के लिए इसमें बदलाव करना संभव नहीं था। काउंसलिंग शुरू होने से ठीक एक दिन पहले नियम और शर्तें, ताकि पहले से ही चयनित उम्मीदवारों को उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के अवसर से वंचित किया जा सके। इसमें कोई संदेह नहीं है यह सच है कि आरक्षित वर्ग में प्रवेश के कई लाभ हैं, लेकिन यह राज्य सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को प्रदान करने के लिए

अपनाई गई नीति का परिणाम है और चूंकि अपीलकर्ताओं का चयन योग्यता के आधार पर किया गया था। लिखित बी परीक्षा के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, श्री पटवालिया ने कहा कि आरक्षित श्रेणी में ऐसे प्रवेश संस्थान में शिक्षा के मानक को बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किए जाने होंगे, जैसा कि ममता मोहंती के मामले में देखा गया था। मामला (सुप्रा), इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। अपीलकर्ताओं ने लिखित परीक्षा में अपने परिणामों के आधार पर चयनित होकर अपनी योग्यता दिखाई है। राज्य के लिए श्री विकास सिंह द्वारा दी गई दलील, कि खुली श्रेणी के अपीलकर्ताओं को एनओसीएस दिया गया था, भी हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि अपीलकर्ता एचसीएमएस की आरक्षित श्रेणी के संबंध में उम्मीदवार थे।

24. तदनुसार, हमें अपील की अनुमति देने और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले और आदेश को रद्द करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हालाँकि, हम उसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसा कि डॉ. विनय रामपाल के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा का सामना किया गया था। इन अपीलों में काउंसलिंग प्रक्रिया 6 अप्रैल, 2011 को आयोजित की जानी थी और शैक्षणिक सत्र 10 मई, 2011 को शुरू होना था। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता पहले ही विचाराधीन पाठ्यक्रमों के लगभग छह महीने खो चुके हैं। जैसा कि डॉ.

विनय रामपाल के मामले (सुप्रा) में देखा गया था, समय की रेत खत्म हो गई थी जो न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य है। उसी तर्क का पालन करते हुए, जैसा कि उपरोक्त मामले में अपनाया गया था, हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त परीक्षण या चयन के नए शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातकोत्तर या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें जी चुना गया है।

25. अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा। एन.जे.

अपीलें निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवाद न्यायिक अधिकारी बृजेश कुमार.1 आर.जे.एस द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।